रोजगार कहाँ हैं मोदीजी?

इस दौर में बढ़ती बेरोजगारी और घटती नौकरियों का सच

बेरोजगारी से तंग आकर गटका विषाक्त, 240 युवा हुए बेरोजगार

SUSHIL KUMAR SINGH

रोजगार के नाम पर युवाओं को गुमरा

बेरोजगारी से तंग आकर दी जान

नवभारत टाइम्स | Updated: Oct 14, 2017, 08:00AM IST

कहानी बेरोज़गार इंडिया की: क्यों लोगों ने नौकरी ढूंढने की कोशिश छोड़ दी?

दुनिया

भारत में नौकरियां घटीं, बेरोजगारी बढ़ी

विकास और आर्थिक प्रगति के तमाम दावों के बावजूद भारत में रोजगार का परिदृश्य और भविष्य धुंधला ही नजर आ रहा है. 2015-16 के दौरान भारत में बेरोजगारी दर बढ़ कर पांच फीसदी तक पहुंच गई जो बीते पांच सालों के दौरान सबसे ज्यादा है.

री से तंग आकर गटका विषाक्त, 240 युवा हुए बेरोजगार

JAR SINGH

नौकरी करने वालों के लिए बुरी खबर, अगले पांच साल में जा सकती है

फर्म क्रिसिलरीसर्च के मुताबिक अगले पांच साल में भारत के आईटी सेक्टर में 6.5 लाख लोगों की नौकरी

आरबीआई का सर्वे: अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों में निराशा बढ़ी, नौकरी सबसे बड़ी चिंता

कहानी बेरोज़गार इंडिया की: क्यों लोगों ने नौकरी ढूंढने की कोशिश छोड़ दी?

आइसा-इनौस प्रकाशन

रोजगार के मुद्दे पर भाजपा नेताओं के कथन

- ''कंपनियों द्वारा रोजगार कम करना, असल में एक बहुत अच्छा संकेत है। हकीकत यह है कि आज, भविष्य का नौजवान महज एक रोजगार ढूढ़ने वाला व्यक्ति ही बने नहीं रहना चाहता,वह तो रोजगार देने वाला व्यक्ति बनना चाहता है। आज देश ऐसे अधिक से अधिक नौजवानों को देख रहा है जो उद्यमी बनना चाहते हैं।''

  पीयूष गोयल, रेल मंत्री
  (06-Oct-2017, PTI)

- ''हम ने रोजगार को नया आयाम देने का प्रयास किया है क्योंकि सवा सौ करोड़ जनसंख्या वाले देश में सब को रोजगार देना संभव नहीं है। हम स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं।''

  अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष
  (27-May-2017, NDTV)

- ''युवाओं को सरकारी रोजगार पाने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। उन्हें स्वरोजगार का अवसर पैदा करना चाहिए और दस अन्य युवाओं को भी रोजगार देना चाहिए।''

  राम माधव, भाजपा नेता
  (16-Oct-2015, Indian Express)

आइसा एवं इनौस के लिए
सुचेता दे और ओम प्रसाद द्वारा U-90 शकरपुर, दिल्ली– 110092 से प्रकाशित

परिचय

दोस्तों, नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा भाजपा सरकार ने 3 साल से अधिक का अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। 'अच्छे दिन' और विदेशों में जमा काला धन वापस लाने जैसे चुनावी वायदों को बहुत पहले ही सरकार ने जुमला घोषित कर दिया है। सरकार के दो सबसे ज्यादा चर्चित आर्थिक सुधार – नोटबंदी और जीएसटी – आम जनता के लिए तबाही भरे साबित हो रहे हैं। नोटबंदी के बाद 99% बंद नोट वापस सरकार के पास आ गए हैं। नोटबंदी के पक्ष में काला धन पकड़ने, नकली मुद्रा का बाज़ार ख़त्म करने, आतंकवाद ख़त्म करने जैसे सरकारी दावे पूरी तरह से फुस्स साबित हुए हैं। दूसरी ओर, जीएसटी के दुष्परिणाम क़ीमतों में बढ़ोतरी, नौकरियों में कटौती और लघु उद्यमियों द्वारा देश भर में उभरे जबर्दस्त गुस्से के रूप में सामने आ रहे हैं।

आज देश की आर्थिक स्थिति हर तरफ़ से घोर अंधेरे में जाती दिख रही है। देश का आर्थिक विकास-दर में तेज गिरावट आ रही है। नौकरियां सृजित करने के मामले में रिकॉर्ड कमी देखने को मिल रही है और कृषि संकट लगातार गहराता जा रहा है। देश में हर घंटे औसतन एक किसान आत्महत्या कर रहा है। (डाउन टू अर्थ, 2 जनवरी 2017) हर मोर्चे पर सरकार को मिल रही भयानक असफलता से जनता का ध्यान हटाने के लिए, मोदी सरकार गाय, बीफ, हिन्दू-मुसलमान और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों को उछाल कर जनता को विभाजित करने पर तुली हुई है। जातिवादी, सांप्रदायिक और सामंती प्रोपेगेण्डा के आधार पर समाज को विभाजित किया जा रहा है।

इस पुस्तिका में, हम विशेष रूप से देश के रोज़गार की बदतर होती जा रही स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे। पुस्तिका में हमारे देश में रोज़गार के निराशाजनक परिदृश्य के बारे में तथ्य, तर्क और विचार प्रस्तुत हैं।

जुमला बनाम वास्तविकता – रोजगार विहीन विकास से 'रोजगार खत्म करने वाला विकास' तक

नवंबर 2013 में, आगरा में एक चुनाव रैली में, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 'अगर भाजपा सत्ता में आई तो हर साल एक करोड़ नयी नौकरियां पैदा करेगी।' भारत में हर साल करीब सवा से डेढ़ करोड़ रोजगार योग्य युवा श्रमिक आबादी तैयार हो रही है। इस चुनावी वायदे ने युवाओं को खासा आकर्षित किया; लेकिन पिछले तीन सालों की वास्तविकता मोदी के चुनावपूर्व उछाले गए जुमलों से पूरी तरह उलट है। सरकार के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि–

- 2015 और 2016 में पिछले आठ साल की तुलना में गहन–श्रम क्षेत्रों में रोजगार की संभावनायें घटकर न्यूनतम दर पर आ गई। 2009 में सृजित किए गए 10 लाख से ज्यादा नये रोजगारों की तुलना में इन दो वर्षों में, केवल 1.55 लाख और 2.31 लाख, रोजगारों का ही सृजन किया गया। (द टेलीग्राफ, 18 मई, 2017)
- 2009–10 और 2010–11 के दो वर्षों की अवधि में लगभग 18 लाख नये रोजगार दर्ज किए गए, जबकि 2014–15 और अप्रैल–दिसंबर 2016 की अवधि में केवल 2.7 लाख रोजगार ही पैदा किए जा सके (द वायर, 17 मई, 2017)। इसलिए 2009 के मुकाबले 2015 और 2016 में जो रोजगार सृजित हुए उनमें 84 प्रतिशत की गिरावट आई है।
- यह हाल तो तब है कि जब वर्तमान सरकार ने डेटा बढ़ा–चढ़ा कर दिखाने की कोशिश में मापदंडों को ही बदलने की कोशिश की है। दिसंबर 2015 के बाद से श्रम ब्यूरो सर्वेक्षण ने अपने सर्वेक्षण में निर्माण, होटल और रेस्तरां जैसे उद्योग व सेवाओं के अधिक से अधिक क्षेत्रों को जोड़ा, लेकिन फिर भी यह रोजगार सृजन में सरकार के निराशाजनक प्रदर्शन को छिपाने में विफल रहा। इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद रोजगारों में अप्रैल–दिसंबर 2016 के दौरान क्रमशः 25000 और 7000 की कमी आ गई थी।
- केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्रालय के आंकडों के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्ष में सूती और हस्तनिर्मित कपड़ा उद्योग के कुल 67 संगठित उपक्रम बंद कर दिए गए। इससे 17600 लोग बेरोजगार हुए। छोटे पैमाने के वस्त्र उद्योगों में यह दृश्य और भी भयावह है।

- देश के सबसे बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी Larsen &Toubro (L&T) ने सितंबर 16'-मार्च 17' में 14,000 कर्मचारियों को काम से निकाल दिया। इसे 'रणनीतिक निर्णय' कहा गया।

अत: यह साफ है कि सरकार द्वारा पकड़ी गई वर्तमान आर्थिक गति 'रोजगारविहीन विकास' से भी आगे जा कर 'रोजगार छीनने वाला विकास' पैदा कर रही है। सरकार की नीतियां न केवल रोजगारों के सृजन में असफल रही हैं बल्कि पहले से ही विद्यमान रोजगारों को भी समाप्त कर रही हैं, यह नीचे दिए गए ग्राफ में और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देता है-

असंगठित क्षेत्र में रोजगार - न कोई कानूनी मासिक भुगतान, न ही सामाजिक सुरक्षा!

यह समझना महत्वपूर्ण है कि नौकरियों या संगठित क्षेत्र के रोजगार से हमारा क्या तात्पर्य है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, जनवरी-अप्रैल 2017 में अनुमानित 40 करोड़ 47 लाख

बदतर होती स्थितियां

आठ सेक्टरों में नयी नौकरियां (संख्या लाख में)

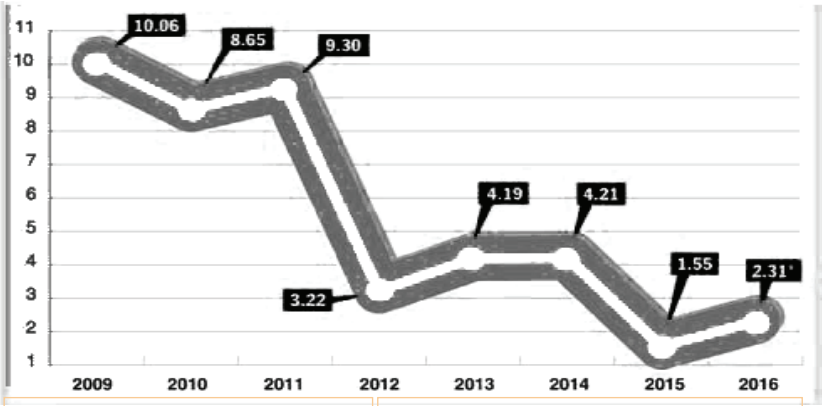

आंकड़ों में 2009 से 2015 तक रोजगार के ये 8 क्षेत्र हैं- कपड़ा, चमड़ा, ऑटोमोबाइल, स्वर्ण व आभूषण, ट्रांसपोर्ट, आईटी/बीपीओ और हथकरघा उद्योग

जनवरी-मार्च 2016 के आंकड़ों में रोजगार के क्षेत्रों को जोड़ दिया गया है। पूर्व के 8 क्षेत्रों के अलावा इसमें निर्माण, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, होटल-रेस्त्रां, आईटी/बीपीओ, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।

लोगों के पास रोजगार था। लेकिन इनमें से केवल 8 करोड़ 60 लाख (21%) लोगों को ही सही मायने में रोजगार मिला हुआ था। इनमें सफेदपोश कर्मचारी, औद्योगिक श्रमिक, कारखानों और कार्यालयों के मैनेजर व सहायक स्टाफ आदि शामिल हैं। बाकी 31 करोड़ 87 लाख नौकरियां असंगठित क्षेत्र में थीं।

संगठित क्षेत्र ही वह नौकरियां हैं जिनकी लोग सही मायने में आकांक्षा रखते हैं। जब कोई सरकार या राजनीतिक दल नौकरी प्रदान करने का वादा करता है या ऐसा संकल्प लेता है, तो उसका तात्पर्य संगठित क्षेत्र की नौकरियों से ही है। बीजेपी ने जब अपने चुनावी वायदे में 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार मुहैया करवाने का संकल्प लिया था तब किसी ने सोचा नहीं था कि इस रोजगार से उनका तात्पर्य खेत मजदूर, निर्माण-स्थलों पर लगे दिहाड़ी मजदूर, ठेला-खोमचा लगाने वाले आदि की संख्या बढ़ाना होगा। सरकार का लक्ष्य था - कारखानों और कार्यालयों में छोटे औपचारिक रोजगार पैदा करना लेकिन इस क्षेत्र में भी नौकरियां तेजी से घट रही हैं।

पिछले कई वर्षों से अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है, यह अर्थव्यवस्था में रोजगार वृद्धि की प्रकृति पर भी विपरीत असर डालती है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार, 2004-05 की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र के रोजगारों का हिस्सा करीब 90 प्रतिशत था।

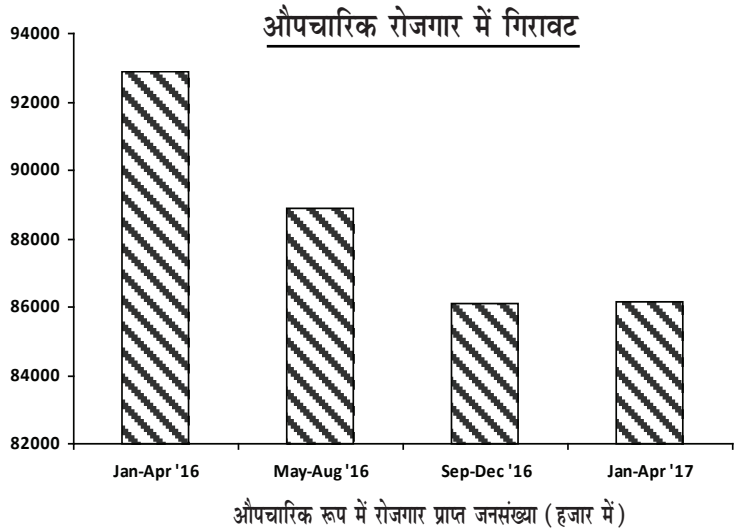

Source: CMIE Website (https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=warticle&dt=2017-07-18%2009:54:00&msec=143&ver=pf)

नेशनल कमीशन फॉर एन्टरप्राइजेस इन द अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह आंकड़ा वर्ष 2017 में 93 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

- जनवरी–अप्रैल 2016 के दौरान, संगठित नौकरियों की संख्या 9.30 करोड़ दर्ज की गई थी। मई–अगस्त 2016 में यह आंकड़ा 8.90 करोड़ तक और सितंबर–दिसंबर 2016 में 8.60 करोड़ तक गिर गया। इस तरह, महज एक वर्ष के अंदर ही संगठित नौकरियों की संख्या में करीब 70 लाख की कमी आ गई (सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इण्डियन इकॉनोमी, 18 जुलाई 2017)।
- इन संगठित नौकरियों से जो लोग बेदखल किए जा रहे हैं उन्हें स्वाभाविक तौर पर असंगठित क्षेत्र में ही रोजगार तलाशने होंगे जो पूरी तरह अनिश्चितताओं से भरा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नौकरी जितनी आसानी से मिल जाती है, उतनी ही आसानी से नौकरी छूटने की संभावना भी हमेशा बनी रहती है।
- कृषि क्षेत्र से भी मजदूरो की बेदखली एक रोजगारविहीन विकास की कहानी कह रही है, जैसा कि सीएमआई की रिपोर्ट बताती है। सितंबर–दिसंबर 2016 और जनवरी–अप्रैल 2017 के बीच, एक ओर जहां जमीन का मालिकाना हक रखने वाले किसानों की संख्या में 37 लाख की वृद्धि हुई, वहीं कृषि मजदूरों की संख्या में 56 लाख की कमी आई। मुश्किल समय में, किसान बाहरी मजदूरों पर निर्भर रहने से बचते रहे। कृषि मजदूरों को किसी भी प्रकार की कोई जॉब सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

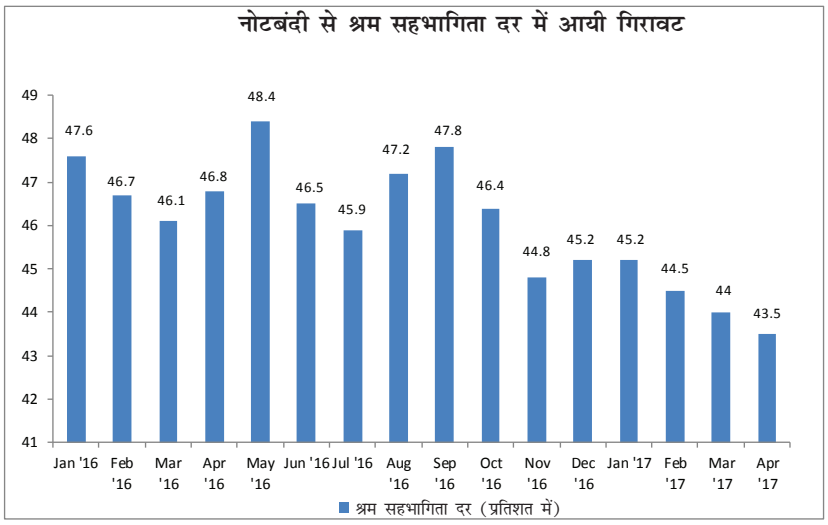

Source: CMIE Website (https://www.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=warticle&dt=2017-07-11%2011:07:31&msec=463)

नोटबंदी से खत्म हुए रोजगार

नोटबंदी को अपनी सफलता के रूप में प्रचारित करने की सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले मगर अर्थव्यवस्था के विविध पहलुओं पर पड़े इसके भयानक असर को यह छुपा नहीं सकती। इसका सीधा दुष्प्रभाव रोजगार पर भी पड़ा। रोजगार पर पड़े नोटबंदी के उल्टे प्रभाव को सीएमआई के आंकड़े स्पष्ट दर्शाते हैं। जनवरी-अप्रैल 2017 के बीच करीब 15 लाख लोगों का रोजगार छिन गया। इससे श्रम सहभागिता दर में आई तीव्र गिरावट आयी है। श्रम सहभागिता दर किसी अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति की सक्रिय सहभागिता दर्शाती है।

जनवरी से अक्टूबर 2016 के दौरान औसत श्रम सहभागिता दर 46.9 प्रतिशत थी मगर नवंबर-दिसंबर 2016 के बाद फरवरी आते-आते यह 44.5 प्रतिशत, मार्च में 44 प्रतिशत और अप्रैल में 43.5 प्रतिशत तक गिर गई। श्रम सहभागिता दर में आई यह गिरावट स्पष्ट दर्शाती है कि इस अर्थव्यवस्था में सक्रिय रोजगार में शामिल लोगों की संख्या कम होती जा रही है। पिछले पृष्ठ पर दिए गए ग्राफिक्स पर गौर करें।

जीएसटी: रोजगार पर और भी बदतर प्रभाव

जीएसटी की जटिलताओं और भारी भरकम टैक्स की राशि के कारण छोटे उद्योग और खुदरा व्यापारी तो बुरी तरह परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन इससे भारी पैमाने पर रोजगार में कटौती भी हो रही है-

- ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में इसकी भारी मार पड़ी है। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट संघ के अनुसार, उनके धंधा में 30-40% की गिरावट हुई है।
- मार्बल, हैंडीक्राफ्ट, स्टील, शिल्पकारी, रिसाइक्लींग इंडस्ट्री आदि पर जीएसटी के बाद जबरदस्त मंदी आयी है, जिसके कारण यहां काम कर रहे दिहाड़ी मज़दूरों की भारी पैमाने पर छंटाई हुई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगारों की क्या हालत है?

जब अनौपचारिक क्षेत्र में स्थायित्वहीन और असुरक्षित रोजगारों का अनुपात बढ़ता जा रहा है, तब हमें सरकार से सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार की स्थिति के बारे में सवाल करने की आवश्यक्ता है।

- भारतीय रेलवे में होने वाली भर्तियों पर सरकार ने एक तरह से रोक लगा रखी है। अकेले केवल ग्रुप-डी में एक लाख से ज्यादा रिक्त पदों को भरने में यह सरकार बुरी तरह विफल रही है (दैनिक भास्कर, 5 अगस्त, 2017। इन पदों पर नियुक्तियां 2014 में ही पूरी हो जानी थीं। पर्याप्त कर्मचारियों की कमी से एक ओर रेलवे की स्थिति बदतर होती जा रही है तो दूसरी ओर दुर्घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है।
- IBPS (इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन) के तहत (स्रोत आईबीपीएस का साइट)

क्लर्कों की बहाली	**बैंक पीओ की बहाली**
2015 -- 24,604	2015 -- 12,434
2016 -- 19,243	2016 -- 8,822
2017 -- 7,883	2017 -- 3,562

- भ्क्थ्ब बैंक में जनवरी-मार्च 2017 के बीच में कार्यरत लोगों की संख्या 90421 से घटकर 84325 हो गई। इससे पूर्व की तिमाही में भी 4581 लोगों की छंटाई की गई थी। निजी क्षेत्र के कमोबेश सभी बैंकों की यही कहानी है। (इंडियन एक्सप्रेस, 4 अक्टूबर 2017)
- ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के मुताबिक हर साल देश भर में तकनीकी संस्थानों से स्नातक होने वाले आठ लाख इंजीनियरों में से 60 प्रतिशत से अधिक बेरोजगार ही रहते हैं।
- 26 जुलाई, 2017 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार रोजगार विनिमय कार्यालयों में पंजीकृत केवल 0.57 प्रतिशत लोगों को ही इस संस्था के जरिये नौकरी मिली है। संख्या के हिसाब से, हर 500 पंजीकृत लोगों में से केवल 3 लोगों को ही पूरे देश में रोजगार विनिमय कार्यालयों के माधयम से रोजगार मिला है।

भारत के आईटी सेक्टर में मची हाहाकार

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बढ़ती संभावनाओं के दौर में भी आज इस क्षेत्र में रोजगार में भारी कटौती हो रही है।

- एक समय तक इस क्षेत्र की कंपनियां 20% का विकास दर आसानी से हासिल कर रही थीं, लेकिन पिछले दो साल से इन्हें 10% का दर हासिल करने में भी मुश्किलें आ गई हैं।

- एक अन्य खतरनाक प्रवृत्ति सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र में छंटनी के रूप में दिखाई दे रही है। एक समय भारत की तथाकथित वैश्विक प्रसिद्धि का कारण बनने के बाद, देश के आईटी क्षेत्र में जबर्दस्त छंटनी का नजारा देखने को मिल रहा है। 2017-18 के वित्तीय वर्ष के प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून, 2017) में टेक महिंद्रा में 1713; इंफोसिस में 1811; TCS में 1414 कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है।
- कार्यकारी खोज फर्म ''हेड हंटर्स इंडिया'' के अनुसार अगले तीन वर्षों में आईटी सेक्टर में नौकरी कटौती की दर सालाना 1.75 लाख से 2 लाख के बीच होगी (14 मई, 2017)।
- डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा (अमेरिकी फर्मों द्वारा विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देने वाला वीजा) पर की गई हालिया कार्रवाई ने पहले से ही मुश्किल चल रहे हालात को और भी बिगाड़ दियाा है।
- वर्तमान परिदृश्य में, आईटी कंपनियां शोषण की नई-नई रणनीतियां तैयार कर रही हैं। कंपनियां उन इंटर्नों को भर्ती कर रही हैं जो या तो अवैतनिक हैं या बहुत कम स्टाईपैन्ड प्राप्त करते हैं। नए-नए स्नातकों को अक्सर 'काम का अनुभव' लेने या बिना वेतन के ही काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।
- चौंकाने वाली बात यह है जब एक ओर भारत में आईटी कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं वहीं 'टेक महिंद्रा' जैसी आईटी कंपनी, जिसने हाल ही में अपने 1713 कर्मचारियों को काम से निकाला है, ने 2000 से ज्यादा अमरीकी कर्मचारियों को काम पर रखा है। कमोबेश यही काम कई आईटी कंपनियों ने किया है। यह सब खेल भारतीय कॉर्पोरेट फर्मों द्वारा ट्रम्प प्रशासन की नजर में आने की कोशिश भर है। ट्रम्प ने तो इस उठापटक पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह तक कह दिया है कि मोदी के 'न्यू इंडिया' का सपना अमेरिका के लिए फायदेमंद है! जाहिर है, अमेरिका का यह फायदा भारत के हजारों आईटी पेशेवरों का रोजगार खा जाने की कीमत पर हो रहा है।

व्यापक बेरोजगारी और अंडर-एम्प्लायमेंट

- अखिल भारतीय स्तर के पांचवें वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 77 प्रतिशत परिवारों के पास नियमित आमदनी या वेतन का कोई स्रोत नहीं है।
- जिनके पास रोजगार हैं भी, उन में से 60 प्रतिशत लोगों को पूरे साल भर के लिए स्थिर नौकरियां या रोजगार नहीं मिलते हैं, जो कि व्यापक स्तर पर अंडर-एम्पलायमेन्ट

नौकरियाँ हैं कहां ?

15 से 29 साल के बीच 30 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय न तो किसी रोजगार में हैं और न ही किसी प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण ले रहे हैं !

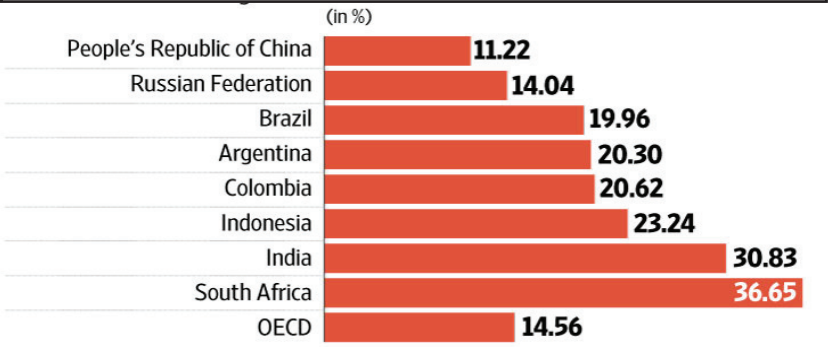

15 से 29 साल के बीच के युवाओं का प्रतिशत जो न किसी रोजगार में हैं और न ही किसी प्रकार की शिक्षा या प्रशिक्षण ले पा रहे हैं !

श्रोत: ओईसीडी आर्थिक सर्वे: भारत 2017

6 अक्टूबर को एक कार्यक्रम में भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने देश की शीर्ष 200 कंपनियों में नौकरियों में हो रही छंटनी पर चिंता जताई और कहा कि इससे देश के संपूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस कार्यक्रम में मौजूद रेलमंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें टोक कर कहा कि – 'अगर देश के टॉप 200 कंपनियों में नौकरियां कम हो रही है तो यह 'शुभ संकेत' है। क्योंकि आज हमारे देश के युवा नौकरी की चाह रखने वाले नहीं बल्कि दूसरों को नौकरी देने वाले बन रहे हैं। आज हर कोई उद्योगपति बनना चाहता है।'

कोई रेलमंत्री को यह बताये कि आम युवाओं के लिए नौकरी का छूट जाना वैसा नहीं होता जैसा मंत्रीजी के लिए मंत्रायल छूट जाना। इन्हें मंत्री पद से हटा भी दिया जाए तो कोई और मंत्रालय, कहीं का गवर्नर या किसी सरकारी संस्थान का चेयरमैन नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन जिन युवाओं की नौकरी सरकार की नीतियों से छूट रही है उन्हें सिर्फ भूख, बेकारी और डिप्रेशन ही मिलता है!

और अस्थायी रोजगार का संकेत है।

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 15-29 आयु वर्ग के 30 प्रतिशत से अधिक युवा रोजगार, शिक्षा या प्रशिक्षण से दूर हैं। इस लिस्ट में उन सभी छात्रों और युवाओं को शामिल किया है जिन्हें वैतनिक रोजगार, औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणालियों के दायरे में नहीं लिया जाता है। भारत रोजगार सृजित करने के मामले में अधिकांश अन्य देशों से बहुत पीछे है। यह आंकड़ा ओईसीडी के औसत (14.56 प्रतिशत) से अधिक है और चीन के (11.22 प्रतिशत) के तो लगभग तीन गुना से भी अधिक है।

मोदी का 'स्किल इण्डिया'- एक जुमला योजना

प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जुलाई, 2015 को 1500 करोड़ रुपये के फण्ड के साथ अपनी बहुप्रचारित 'स्किल इण्डिया' योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य लिया गया। लेकिन इस योजना के पहले चरण में केवल 5 प्रतिशत ही प्लेसमेंट देखा गया, उसमें से भी अधिकतर शहरी क्षेत्रों में मेहनत-मजदूरी का काम ही था। योजना शुरू होने के साल भर बाद सरकार ने दावा किया कि 'स्किल इण्डिया' कार्यक्रम के तहत लगभग 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स की जांच (जो 2 मार्च 2017 को प्रकाशित हुई) के साथ ही शारदा प्रसाद की अध्यक्षता वाली सरकार की अपनी कमिटी की रिपोर्ट (दिसंबर 2016 में प्रस्तुत) ने इन दावों की पोल खोल दी-

- 2014-15 में कुल 4 लाख 47 हजार 350 पंजीकृत नौजवानों में से महज 873 (0.19 प्रतिशत) को ही विविध क्षेत्रों में रोजगार मिल सका।
- जवाबदेही और निगरानी के अभाव में निजी 'स्किलिंग शॉप्स' द्वारा 1500 करोड़ रुपये की सार्वजनिक राशि का जमकर दुरूपयोग किया गया। घटिया बुनियादी ढांचे वाले फर्जी प्रशिक्षण केन्द्रों ने जमकर पैसे लूटे। दूसरी ओर, योजना के पहले चरण में प्रमाणित 12,181 संस्थानों की संख्या को घटाकर दूसरे चरण में केवल 1400 कर दिया गया। ऐसे में अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर

'प्रशिक्षण केन्द्र' खोलने वाले लोगों पर संकट आ गया।

- 'कौशल भारत' ने प्रशिक्षित प्रशिक्षक बनाने के लिए नए-नए डिप्लोमाधारी और इंजीनियरिंग स्नातकों को केवल 2 से 5 दिन का प्रशिक्षण दे कर ही मान्यता प्राप्त प्रशिक्षक बना कर बाकी काबिल प्रशिक्षकों का मजाक बना डाला।
- पूरी योजना का कोई सही आंकड़ा न तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के पास है न तो सरकार के पास। प्रशिक्षितों के नामांकन और उनकी संख्या में भी भारी फर्जीवाड़ा सामने आया है।

स्टार्टअप इंडिया, एक फ्लॉप शो

स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम जनवरी 2016 में शुरू किया गया था ताकि युवा उद्यमियों को अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्त उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन सरकार की नीतियों के चलते-

- 2016 में कुल 212 स्टार्टअप बंद हो गयें। यह 2015 में बंद हुए स्टार्टअप की तुलना में 50% अधिक हैं।
- Stayzilla और Taskbob जैसे बड़े स्टार्टअप 2017 में बंद हो गयें।
- 2017 के जनवरी से सितंबर तक कुल 800 स्टार्टअप चल रहे हैं। पिछले साल इसी समय-सीमा में यह 6000 थे। बाकी के सब बंद हो चुके हैं।
- स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई लोगों ने अपनी पिछली अच्छी-खासी नौकरियां भी छोड़ दी थीं। लेकिन, कई स्आर्टअप विफल होने के बाद से, वे अब बेरोजगार हो गए हैं (द इकोनॉमिक टाइम्स, 12 सितंबर, 2016)।

चौतरफा हमला : बाल मज़दूरी को वैधता, मातृत्व लाभ में कटौती और श्रम कानूनों से खिलवाड़-

बाल मज़दूरी को वैधता

युवाओं को रोजगार देने में विफल सरकार अब बाल-श्रम को बढ़ावा दे रही है-

- 2016 तक 'बाल-श्रम कानून' के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी काम पर लगाने की पाबंदी थी। 2016 में मोदी सरकार ने इसमें संशोधन कर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को भी गैर-खतरनाक 'पारिवारिक उद्यमों' में काम करने की अनुमति दे दी। संशोधन में 'परिवार' की परिभाषा के तहत बच्चों के मां-बाप और भाई-बहन तो हैं ही, मां-बाप के भाई-बहन भी हैं।

- 2016 के संशोधन में 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों के लिए 'खतरनाक कार्य में रोजगार' को निषिद्ध किया गया है; लेकिन इस मामले में बड़ी चालाकी से 'खतरनाक कार्य' की परिभाषा ही बदल दी गई है। इसके तहत 83 प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची को अब महज 3 की संख्या तक सीमित कर दिया गया है।
- सरकारी विचारकों का कहना है कि 'पारिवारिक' उद्यमों में बाल श्रम की अनुमति देने वाला खंड बच्चों को अपने माता-पिता के व्यवसाय को सीखने की अनुमति देगा। असल में यह तर्क जाति व्यवस्था का बचाव करता है जो कहती है कि व्यापार जन्म के आधार पर बच्चों की विरासत बन जाना चाहिए। जैसा कि हर्ष मंदर पूछते भी हैं, ''कुम्हार का बच्चा कुम्हार ही क्यों होना चाहिए, कवि क्यों नहीं, एक सफाईकर्मी का बच्चा डॉक्टर क्यों नहीं और चर्मकार का बच्चा दार्शनिक क्यों नहीं होना चाहिए?'' ये संशोधन भारत की असमान बचपन की प्राचीन परंपरा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक और कदम के बतौर ही समझा जाना चाहिए।

मातृत्व लाभ में कटौती : भारत माता की जय?

2017 के नव वर्ष की पहली शाम को दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरानी मातृत्व लाभ की योजना को 'नयी योजना' कह दिया। इस पूर्ववर्ती योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में रहने, टीकाकरण और पोषण के लिए 6,000 रुपये मिलते हैं।

- अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट में, महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा था कि 2016-17 में 200 जिलों तक पहुंच बनाने के साथ ही यह योजना सभी जिलों तक विस्तारित की जाएगी। मगर मोदी सरकार ने इस वादे को पूरा नहीं किया है।
- मोदी सरकार ने 26 सप्ताह के वैतनिक मातृत्व अवकाश को संगठित क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं के लिए ही सीमित कर दिया। असंगठित क्षेत्र में काम कर रही करीब 95 प्रतिशत महिलाओं को छोड़ दिया गया।
- इस योजना के तहत सभी महिला कर्मचारियों को कवर करने हेतु 16,000 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट की आवश्यकता जताई गई, लेकिन सरकार ने सिर्फ 2,700 करोड़ रुपये ही आवंटित किए हैं, यानि आवश्यक बजट का एक चौथाई भी नहीं।
- आश्चर्यजनक तरीके से मोदी सरकार ने मातृत्व सहायता योजना के लाभ को किसी मां के केवल पहले सुरक्षित प्रसव तक ही सीमित करने का फैसला किया है। इस योजना में पहले दो सुरक्षित प्रसवों तक यह लाभ मिलता था; महिला संगठन यह मांग है कि ये लाभ सभी प्रसवों हेतु दिए जाएं।

श्रम कानूनों पर हमलावर सरकार

कॉर्पोरेट्स के लिए 'व्यावसायिक सहूलियत' देने के नाम पर मोदी सरकार श्रमिक अधिकारों को कमजोर करने या पूरी तरह समाप्त कर देने पर तुली हुई है–

- 13 मारूति मज़दूरों को यूनियन बनाने और न्यूनतम वेतन की मांग उठाने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस मामले में सरकार के वकील ने कोर्ट से मजदूरों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी, जबकि कंपनी की ओर से किये जा रहे श्रम कानूनों के उल्लंघन पर उसने चूं तक नहीं की।
- भाजपा शासित राजस्थान में औद्योगिक विवाद अधिनियम अब 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना ही श्रमिकों को काम से निकाल देने या तालाबंदी करने की अनुमति देता है। इससे पहले, 100 से ज्यादा कर्मचारियों वाली कंपनियों को ही ऐसा करने की अनुमति दी गई थी।
- कारखाना अधिनियम अब तक ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू होता था जो बिजली का उपयोग करते हो और 20 श्रमिकों को रोजगार देते हों या फिर जो बिजली का उपयोग नहीं करते हों और 40 श्रमिकों को रोजगार देते हों। पहले यह संख्या क्रमशः 10 और 20 थी।
- राजस्थान सरकार ने यूनियनों के लिए मान्यता प्राप्त करना भी कठिन बना दिया है। अब पूरे देश भर में 'राजस्थान मॉडल' को लागू करने की तैयारी है।
- मोदी सरकार ने बड़ी बेशर्मी से कंपनियों को 'आत्म-प्रमाणन' की मंजूरी दे दी है। यानि अब श्रम विभाग द्वारा निरीक्षण के बजाय किसी भी कंपनी का मालिक प्रतिवर्ष खुद ही यह प्रमाणित करेगा कि उसकी कंपनी सभी श्रम कानूनों का पालन कर रही है।
- मोदी सरकार कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत ठेका मजदूरों को भी समान वेतन देने के मुद्दे पर ट्रेड यूनियनों की लंबे समय से लंबित मांग को अस्वीकार करती रही है। इसकी बजाय वे कह रहे हैं कि सभी ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा! लेकिन कानून तो पहले से ही न्यूनतम वेतन की बात करता है।
- मोदी सरकार ने 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है, जिसमें न्यूनतम मजदूरी में अब तक की सबसे कम वेतन वृद्धि की सिफारिश है।
- सरकार लगातार लाखों आंगनवाड़ी, मिड-डे मील, आशा, पैरा-शिक्षकों और अन्य लोगों को मजदूरों के रुप में मान्यता देने से इंकार कर रही है। इस प्रकार उन्हें कानूनी न्यूनतम मजदूरी नहीं देने के लिए भी सरकारों को छूट है। दूसरी ओर, इन योजनाओं के लिए धन के आवंटन को बजट दर बजट घटाया जा रहा है।

नौकरियां कहां हैं मिस्टर मोदी?

मोदी सरकार ने 26 मई, 2017 को देश भर के अखबारों के फ्रंट पेज पर अपनी 'उपलब्धियों' का एक विज्ञापन जारी किया। इसमें उन्होंने देश के युवाओं के लिए लिखा था– 'एक नए भारत की ताकत, युवा शक्ति'। लेकिन आश्चर्य की बात है कि युवाओं के लिए पिछले तीन सालों में कितनी नौकरियों का निर्माण हुआ, इस बात का कोई जिक्र ही नहीं है। विज्ञापन में कहा गया कि लगभग 1 करोड़ युवाओं के लिए 'कौशल भारत योजना' और 'स्टार्ट–अप इंडिया' के तहत प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं जबकि सरकार के अपने आंकड़े और रिपोर्ट के आधार पर भी ये दोनों योजनायें 'फ्लॉप शो' साबित हो चुके हैं।

हमें 'युवा शक्ति' का जुमला उछालने वाली इस सरकार से सवाल करना चाहिए कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या किया है? सरकार पिछले तीन सालों में हर बार जारी किए गए अपने रिपोर्ट कार्ड में सृजित किए गए रोजगारों की संख्या के बारे में चुप क्यों है? श्रम और रोजगार मंत्री, बंडारू दत्तात्रेय ने स्वीकार किया कि मौजूदा विकास रोजगारविहीन विकास है और देश में रोजगार सृजन के बारे में उनके पास कोई डाटा भी नहीं है। (द हिंदू बिजनेस लाइन, 31 मई 2017) सवाल है कि क्यों यह सरकार बेरोजगारों की फौज खड़ी करने वाली नीतियों पर चल रही हैं?

दरअसल, यह सरकार विश्व पूंजी और उसके बाजार के लिए भारत की युवा शक्ति को सस्ते श्रमिक में बदल देना चाहती है। यही कारण है कि संगठित क्षेत्र में नौकरियों की संभावनाओं को न्यूनतम बनाया जा रहा है तो दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के श्रम अधिकारों पर निरंतर हमला साधा जा रहा है। एक ओर मंशा की कमी के चलते रोजगार आधारित सरकारी योजनायें बुरी तरह विफल हो रही हैं तो दूसरी ओर नोटबंदी और जीएसटी जैसी नीतियों से लाखों लोगों को बेकार बनाया जा रहा है। बेरोजगारों की जितनी बड़ी फौज होगी, देशी–विदेशी पूंजीपतियों को उतने सस्ते मजदूर मिलेंगे। लाखों रिक्त पदों को भरने में नाकाम इस सरकार ने 2016–17 के दौरान बड़े कॉर्पोरेट को 83492 करोड़ रुपए की छूट दे दी। आखिर भाजपा सरकार की देशभक्ति का ये कैसा पैमाना है जहां युवाओं के भविष्य को अंधकार में ढकेलकर कॉर्पोरेट को खजाना दिया जा रहा है!

भीड़ है, नौकरी नहीं!

हमने देखा कि कैसे रोजगार सृजन के लिए 2014 में किए गए बीजेपी के चुनावी वादे बुरी तरह विफल हो गए हैं। किसानों, मजदूरों, छात्रों और नौजवान वर्ग के अधिकारों पर निरंतर हमले हो रहे हैं। हाल के दिनों में मोदी सरकार की लोक-विरोधी नीतियों के खिलाफ उन किसानों, श्रमिकों, छोटे व्यापारियों, छात्र-नौजवानों को बड़े पैमाने पर आंदोलन करते देखा है जो सस्ती शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार की मांग कर रहे हैं। ऐसे आंदोलनों को तोड़ने के लिए, असंतोषपूर्ण आवाजों को चुप कराने के लिए भाजपा-संघ एक ओर आंदोलनों पर बर्बर लाठी-चार्ज कर रही है तो दूसरी ओर, 'फूट डालो और राज करो' की अंग्रेजों की नीति द्वारा लोगों को विभाजित किया जा रहा है। सत्तारूढ़ शक्तियों ने जातिवादी-सांप्रदायिक नफरत को फैलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हिंसा को मजबूत करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों व अन्य हाशिए के समुदायों पर भयावह हमलों और 'मॉब लिंचिग' को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक ओर कॉर्पोरेट लूट चलती रहे तथा दूसरी ओर शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, काला धन जैसे मुद्दों पर जनता एकजूट न हो पाए इसलिए सरकार बेशर्मी के साथ हिंदू-मुसलमान और 'देशभक्त'-'देशद्रोही' के आधार पर उन्हें आपस में ही उलझाए रखने की साजिश रच रही है।

किसी भी लोकतंत्र की नींव के रूप में सुलभ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सम्मानजनक रोजगार को देखा जाना चाहिए। हमें मौजूदा शासन से यह पूछना चाहिए कि क्या देश छात्रों के लिए शिक्षा में फीस वृद्धि, सीट कटौती और छात्रवृत्ति खत्म करना तथा दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स को लाखों करोड़ की छूट देना ही उसका राष्ट्रवाद है? क्या रोजगार में कटौती करना और बेरोजगारी बढ़ा कर भारतीय युवाओं के भविष्य को अंधेरे में डाल देना ही राष्ट्रवाद है?

अंधेरे समय में भी गीत गाए जाएंगे!

दोस्तों, यदि यह जुमलों और रोजगार छिनने वाला विकास, जीएसटी और नोटबंदी जैसी आपदाओं का दौर है, तो साथ ही यह छात्र-नौजवानों, महिलाओं, किसानों, मजदूरों के ऐतिहासिक संघर्षों का भी समय है। पिछले साल 2 सितंबर को हुई ऐतिहासिक आम हड़ताल और पूरे देश में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शनों ने श्रम कानूनों को कमजोर करने की सरकार की कोशिशों को कुछ हद तक पीछे धकेला है। आईटी उद्योग के इतिहास में पहली बार, कर्मचारी खुद को संगठित

करने, याचिकाएं दर्ज करने, यूनियन बनाने और अपनी समस्याओं को राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेंगलुरु के कपड़ा उद्योग में महिला श्रमिकों ने अपने ऐतिहासिक आंदोलन द्वारा अपनी गाढ़ी कमाई के पीएफ का पैसा वापस पाया। देश के अलग-अलग हिस्से में रेलवे बैंकिंग आदि में लंबे समय से लंबित नियुक्तियों के विरोध में छात्रों-नौजवानों का भारी आक्रोश देखा गया है। भारत के लोग आज एकजुट हो रहे हैं, यूनियन बना रहे हैं और सरकारी दमन के खिलाफ मुकाबले में साहसिक वापसी कर रहे हैं।

आज, जब मुख्यधारा के मीडिया सहित हमारे लोकतंत्र के अधिकांश संस्थान लाचार और बिकाऊ साबित हो रहे हैं, तब लोकतंत्र और जन-अधिकार की रक्षा के लिए जगह-जगह चल रहे भारतीय जनता के साहसिक संघर्षों में आशा की किरण नजर आती है। देश भर में, मोदी शासन के तानाशाही रवैये के खिलाफ एकजुट संघर्ष बढ़ रहे हैं। आज छात्र-नौजवानों को इस संघर्ष में हिरावल भूमिका निभाने की ऐतिहासिक जरूरत है। आइये, भारत में लोकतंत्र, अधिकार, बराबरी और सम्मान के लिए चल रहे प्रतिरोधों को तेज करने की हमारी प्रतिज्ञा को नई ताकत दें।

नफरत नहीं अधिकार चाहिए
शिक्षा और रोजगार चाहिए

भीड़ नहीं रोजगार दो!
रोजगार को मौलिक अधिकार का दर्जा दो!!

रोजगार कटौती पर तुरंत रोक लगाओ!
सलाना एक करोड़ नौकरियों का वादा निभाओ!!

रोजगार के नाम पर युवाओं को गुमराह कर रही सरकार
भारत में नौकरियां घटीं, बेरोजगारी बढ़ी
स्तंभ
आरबीआई का सर्वे: अर्थव लोगों में निराशा बढ़ी, नौक बड़ी चिंता
बढ़ती बेरोजगारी और किसान आत्महत्या मोदी सरकार की विफलता
11 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंची बे
Posted By: Anujkumar Maurya
Updated: Tuesday, October 10, 2017, 18:36
कोशिश छोड़ दी?
मोदी सरकार के 3 साल: रोजगार के मोर्चे पर सरकार कितनी सफल?
IT सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए बुरी खबर, अगले पांच साल में जा सकती है 6.5 लाख लोगों की नौकरी
नौकरी ढूंढने की
स्तर पर पहुंची बेरोजग
Posted By: Anujkumar Maurya
Updated: Tuesday, October 10, 2017, 18:36 [IST]
कहानी बेरोज़गार इंडिया की: क्यों लोगों ने नौकरी ढूंढने की कोशिश छोड़ दी?

सहयोग मूल्य – रु. 5